एडवांटेज विदर्भ

विकास के मामले में पिछड़े विदर्भ की तस्वीर बदलने की शानदार पहल हुई। एडवांटेज विदर्भ की बैठक में देश के जानेमाने उद्यमी शरीक हुए। मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण ने मेजबानी की। औद्योगिक विकास की उड़ान भरने के वादे के साथ राजनीतिक इच्छा शक्ति में जोश भरने का प्रयास किया। कुछ उद्यमियों व जनप्रतिनिधियों ने सरकार के कान खींचने के प्रयास भी किए।

शुभारंभ
मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण ने सुबह 9.45 बजे फीताड़ी लांगे की उपस्थिति में दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की।

डॉलर आकर्षण
हेरिटेज मेगा प्लांट का मध्यपूर्व अर्थात् उद्योगपति, नेताओं से खचाखच भरा हुआ था।

होटल में ही ठहरे उद्योगपति
मंत्रियों और उद्योगियों के ठहरने की व्यवस्था होटल में ही की गई थी।

सिरकत
कई प्रमुख ऑटो कंपनियों के कई अधिकारियों ने भी शिरकत की। कार्यक्रम के पहले दिन दूसरे सत्र में नागपुर दि नेक्स्ट ऑटोमोबाईल हब पॉसीबिलिटीस एंड अपॉरच्युनिटीस विषय पर चर्चा हुई। पक्कड़ों ने नागपुर को परिपूर्ण का ऑटो हब बताया।

सहयोग मिलेगा
विदर्भ में बिजली, पानी, कोयला, पत्थर भरपूर मात्रा में है। मल्टीनेशनल इंडस्ट्री के लिए काफी पोटेंशियल है। जानकारी है उद्योगियों द्वारा निवेशकर्ता लेने की। सरकार उद्योगियों को हर संभव सहयोग देने को तैयार है।
-सत्यनारायण, निदेशक, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया

रोजगार मिलता है
मौदा में एनटीपीसी का जो प्रोजेक्ट पूरा हुआ है, उसमें लगभग 500 कुशल कामगारों व 500 अकुशल कामगारों को रोजगार मिला है। एनटीपीसी का उद्देश्य बिजली के साथ ही यहां रोजगार के अवसर निर्माण करना भी है।
-बी. वेंकटरमैंडियन, महाप्रबंधक एनटीपीसी

24 घंटे मिलेगी बिजली
उद्योगों को 24 घंटे बिजली मिलेगी। लघु व मध्यम उद्योगों को सस्ती बिजली दी जाएगी। प्रति यूनिट 1 रुपए सब्सिडी दी जाएगी। यहां बिजली की कोई कमी नहीं है।
-अजीत मेहता, प्रधान सचिव, ऊर्जा विभाग

विकास जरूरी
औद्योगिक विकास के लिए राजनीतिक, सांस्कृतिक व प्रशासकीय विकास आवश्यक है। इस दिशा में सभी को प्रयास करना चाहिए।
अतुल भातखे, पोद्दार मानसि सुतुबी

इंटीग्रेटेड पार्क बनें
चंद्रपुर में उद्योग टुकड़ों में बटे हुए हैं। इससे परिवहन का किराया बढ़ जाता है। इन्हें एक साथ लाने की आवश्यकता है। इसके लिए महिंद्रा व होंडा जैसे विकास जरूरी है। इंटीग्रेटेड पार्क की जरूरत है।
- एस. के. गुप्ता, हुए मोगासी, रेमंड यूनिवर्सल डायरेक्ट लिमिटेड

खलती है कमी

...तो बात बन जाए

प्रस्तुति : टीम भास्कर, नागपुर

16 कंपनियों के साथ उद्योग विभाग का 14,482 करोड़ का एमओयू

कंपनी	उत्पादन	एमओयू करोड़ रु. में
पोस	कार्बो	2500
अंबुजा सीमेंट, चंद्रपुर	सीमेंट	3300
व्हिसकास सीमेंट, चंद्रपुर	सीमेंट	1500
ओमा आयरन स्टील, चंद्रपुर	लोहा	1000
व्हाईसाल इंडस्ट्रीज्स	स्टील	600
मुर्गोलमी कॉटन मिल, नागपुर	वस्त्र	500
पुनवटे पेपरे प्रा. लिमिटेड	लोहा	400
मलकीत आयरन लिमिटेड, चंद्रपुर	लोहा	340
सिंडालको इंडस्ट्रीज लि. सौदा	एल्युमिनियम	318
इंडस कृषा इंफ्रास्ट्रक्चर लि., नागपुर	पुल निर्माण	311
सुलभ फूड्स प्रा. लि. चन्द्रपुर	खाद्य सामग्री	114
आर. बी. पन्नालिक नागपुर	पन्नालिक	102
सूर्या सिमेंटिंग लि. नागपुर	रसायन	92.80
आर. एम. मोहता कंपनी शिवणघाट वस्त्र		45
महा मिनरल प्रा. लि.	आक्सीजन	140
रमशेका प्रोटीन्स	खाद्य सामग्री	98

आर्थिक कारणों से निर्माण का शेड्यूल को मुख्य अतिथि उद्योग मंत्री कुमार अंबेकरजी के हाथों एमओयू देव अमोल साहबांत प्रस्ताव दिया गया है।

700 उद्यमियों ने कराया पंजीयन

एडवांटेज विदर्भ के दौरान आयोजित विशेष वस्त्र उद्योग उद्यमियों ने पंजीयन कराया है। इसके लिए आयोजन स्थल पर प्रतिनिधि नियुक्त किए गए थे। सुबह 8 बजे से ही बड़ी तादाद उद्यमियों की पंजीयन प्रक्रिया शुरू थी।

वस्त्रोद्योग में 1880 करोड़ का करार

■ 2012 में बनी टेक्सटाइल्स पॉलिसी में होगा बदलाव ■ विदर्भ के कपास उत्पादक जिलों में कॉमन एफ्लूयेंट प्लांट का निर्माण

श्री. अतिश शाह

टेक्सटाइल कमिश्नर श्री. अतिश शाह ने टेक्सटाइल डिपार्टमेंट के प्रेजेंटेशन को नई टेक्सटाइल पॉलिसी के अनुसार बनाने की घोषणा की है। सेंटर फॉर एक्सीलेंस में अपेक्षित पात्र परिसर में अपेक्षित श्री. अतिश शाह ने बताया कि एमआईडीसी विदर्भ के सभी कपास उत्पादक जिलों में कॉमन एफ्लूयेंट प्लांट का निर्माण करेगी। सूतगिरणी उद्योग को बिजली में 1 रुपए तक की छूट प्रदान की जाएगी। एडवांटेज विदर्भ के दौरान कुल 18 हजार करोड़ रुपए के एमओयू हुए हैं, जिसमें से 1880 करोड़ के एमओयू टेक्सटाइल्स इंडस्ट्री के लिए हुए हैं।

(वर्ष 2012 में टेक्सटाइल्स पॉलिसी बनी थी, जिसके तहत 310 प्रोजेक्ट बनाए गए थे। इनमें 27164 करोड़ रुपए का कुल बोझ है। विदेश हुआ था इसके माध्यम से 31 हजार लोगों को रोजगार प्राप्त हुआ।)

इन उद्योगों ने किए विस्तार अनुबंध

कंपनी	उत्पादन	अनुबंध करोड़ में
मे.भूषण स्टील लि. बुटीबोरी	स्टील	1350
ग्रीन्स फिल्मेस ट्रस्ट्स प्रा.लि. देवरी	ट्रस्ट्स लाइट	300
मे. ओमकोल लि.बुटीबोरी	फाय	290
मे.एच.एम इंडस्ट्रीज लि.अमरावती	फाय	280
श्याम इंडो पेक्स लि.अमरावती	फाय	273
रेमंड्स यूको डेनिम प्रा.लि. फत्तेपवान फाय		250
इंजीनियरिंग टेक्सटाइल्स प्रा.लि बुटीबोरी फाय		150
विदर्भ सोया सिल्क फत्तेपवान	खाद्य प्रक्रिया	100
सोपुरी इंडस्ट्रक्चर	लॉजिस्टिक	300

विस्तारित प्रकल्प को कैपिटल सब्सिडी

वस्त्रोद्योग की जरूरतों पर उद्योगपतियों ने रखी राय

एडवांटेज विदर्भ के तहत 'विदर्भ में वस्त्रोद्योग की संभावना' विषय पर चर्चा हुई। मे. अतिश शाह ने प्रोजेक्शन बताते हुए कि जिनिंग प्रोसेसिंग को महाराष्ट्र सरकार द्वारा सब्सिडी दी जाएगी। साथ ही केंद्र सरकार की वस्त्रोद्योग योजना 'टफ' से महाराष्ट्र राज्य को दुगुनाई से जोड़ा जाएगा। उद्योगों को बी-एमएम जोन की सुविधाएं प्रदान करने की गिनाई है। रेडिमेड वस्त्रों का उत्पादन बढ़ाने पर ध्यान दिया जाएगा। वार्तालाप में उद्योगों के अतिरिक्त ऑपरेशन पद्धति से परीक्षाएं ले रहे हैं। इसके जरिए अब तक 319 प्रस्तावों को मंजूरी दिया गया है, जिनमें लगभग हजार लोगों को रोजगार मिला है और 2 हजार 149 करोड़ का निवेश किया गया है। उद्योगपतियों ने भी विचार व्यक्त किए।

इच्छाशक्ति से होगा उद्योगों का विकास

विदर्भ में उद्योग के लिए अनुकूल माहौल है, लेकिन इच्छाशक्ति व राजनीतिक मंशा की जरूरत है। पूंजीवादी की हड़ताल में व्यवस्था उद्योगों को काफी दर्द दे गई है। विदर्भ में अगर उद्योगों को बढ़ावा देना है, तो सबसे पहले उद्योगों को सहयोग में बेहतर वातावरण नहीं अगर उद्योगों में तीसरे सेक्टर में सुधारकर विकास होगा।

सही दाम नहीं मिल रहा

विदर्भ के कपास को इंट्रा लाभ नहीं मिलने से सही दाम नहीं मिल पा रहा है। सुताबार के कपास पर देश भर में विशेषता 'सेवर' लगाकर इंट्रा का लेबल लगा हुआ है। इससे मुख्य आंकड़ा है, जबकि इसकी गुणवत्ता विदर्भ के कपास जैसी ही है। कपास का मुल्य बढ़ाने के लिए उस पर इंट्रा का उत्पादन का लाभ लगाया जाएगा है।
- सुरेश कोटक, अध्यक्ष, कोटक कार्पोरेशन

सिंगल विंडो जरूरी

कपास के बीज की उपलब्धता पर अतिश शाह ने भी उपलब्धता है। साथ के रूप में भारत में अलावी से उत्पन्न होनेवाले जीन का उत्पादन वातावरण सहित हो सकता है। इंडस्ट्री फ्रेंडली वातावरण के लिए सिंगल विंडो सिस्टम में लाया जाना जरूरी है।
- दिलीप जीवराजका, प्रबंध निदेशक, आनंदम इंडस्ट्री लिमिटेड

इंटीग्रेटेड पार्क बनें

नुकसानी में बटे उद्योगों को साथ लाने की आवश्यकता है। इससे परिवहन का किराया बढ़ जाता है। पॉलिसी व इंफ्रास्ट्रक्चर विकास के साथ इंटीग्रेटेड पार्क की उपलब्धता है। वार्तालाप में उद्योगों के विकास के लिए उत्तीन पार्क टेढ़ी खीर है।
- एस. के. गुप्ता, हुए मोगासी, रेमंड यूनिवर्सल डेनिम डायरेक्ट लिमिटेड

वैट कम करें

वार्तालाप को निवेश के लिए प्रोत्साहन सुविधाएं उपलब्ध वातावरण होना। वैट को खत्म कर इसे पेट्रोल बनाने का भी प्रावधान होना चाहिए।
- संदीप गुप्ता, मनेजिंग पार्टनर, इण्डस टेक्सटाइल प्राईवेट लिमिटेड

पॉवरलूम का आधुनिकीकरण हो

क्लेरिटी लाइन का उत्पादन वातावरण उपलब्ध बढ़ाने में सहायता है। महाराष्ट्र में पिजिंग की सुरक्षता को बढ़ाए जाने की जरूरत है। पॉवरलूम का आधुनिकीकरण आवश्यक है।
- अविनाश मोहकर, सुविधा एडवाइजर

इंटीग्रेटेड सेटअप लगाएं

ऊर्जा पर सब्सिडी देने की आवश्यकता है। विदर्भ में एग्रोबेस के लिए अच्छी में वातावरण, सोयाबीन, सब्जियों उत्पादन मौजूद है। उद्योग के विकास के लिए इंटीग्रेटेड सेटअप लगाया जाए।
- के. के. अग्रवाल, अध्यक्ष भारतीय इंडस्ट्री लिमिटेड

बने लचीली योजना

वार्तालाप में उद्योगों के लिए लचीलेपन का इन्फेलमन हो रहा है, लेकिन मजदूरों की सही दिशाबोध है। सरकार को चाहिए कि मजदूरों के लिए लचीली योजनाएं बनाए।
- महेश कोठारी, एडमीनिस्ट्रेटिव डायरेक्टर, फाल्कनेक्स

कैपिटल पॉवर प्लांट बनें

कैपिटल पावर प्लांट लगाए जाने चाहिए। विदेश से प्रोसेसिंग तकनीकों को बढ़ावा होना। विदर्भ क्षेत्र में सब्जियों उत्पादन बढ़ाने से इसका विकास संभव है।
प्रशांत कुमार मोहता, प्रबंध निदेशक, पोमोना, इंडस्ट्री डायरेक्ट लिमिटेड

खास क्षेत्रों पर हो ध्यान

उत्पादन, पुल, पोल, पॉवर, जनुल, उर्जा, पैकेज तैयार माल क्षेत्रों पर ध्यान आकर्षित करने की जरूरत है। नए प्रस्तावों के लिए डिटेल्ड सब्सिडी दिया जाना चाहिए। सरकार पुलिस बनाया जाना चाहिए।
- सुनील पोद्दार, प्रबंध संचालक, टेक्सटाइल, नागपुर

नागपुर भविष्य का ऑटो हब

टाटा संस के चेयरमैन सायरस मिस्त्री

एडवांटेज विदर्भ के दो दिवसीय सम्मेलन में मे टाटा संस के चेयरमैन सायरस मिस्त्री सहित कई बड़े उद्योगपति पहुंचे। श्री मिस्त्री ने कहा कि टाटा ग्रुप ने नागपुर में ही टेक्सटाइल क्षेत्र की शुरुआत की थी। वार्तालाप में मे टाटा मोटर्स्टोरी लिमिटेड का विलाप में प्रोजेक्ट है, जिसमें लगभग 600 करोड़ का निवेश कर रही है। टाटा टेलिसर्विस द्वारा मेट्रोसिटी योजना पर टेलिकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर लाभ में आवासीय और व्यावसायिक परियोजना का काम जारी है। विदर्भ में पर्यटन क्षेत्र में भी टाटा की भौजूदगी है। पेंच स्थित ताडोबा रिजर्व में योजनों के पर्यटन पर्यटकों के लिए उपलब्ध कराए हैं। उन्होंने भविष्य में योजनों की विदर्भ में विलास योजनाओं के बारे में कोई संकेत नहीं दिए। श्री मिस्त्री से मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण को एडवांटेज विदर्भ के आयोजन कि लिए बधाई दी और उद्योगों को यहां आकर्षित करने के लिए धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि विदर्भ में राज्य का औद्योगिक विकास यहां की सरकार की नीतियों पर ही निर्भर करता है। नीतियां उद्योगों के लिए यदि लाभकारी होती है, तो निश्चित ही उद्योग यहां आकर्षित होंगे।

भविष्य में होगा विस्तार

अमेरिका लेनोवो की मौजूदगी विदर्भ में है। यहां ऑटो क्षेत्र के लिए भविष्य में संभावनाएं है, जिसे देखते हुए योजनों की यहां भविष्य में विस्तार की योजनाएं है। योजनों को विदर्भ में अच्छा अनुकूल मिला है।
- एस. वी. तिवारी, कॉर्पोरेट कम्यूनल मैनेजर, अमेरिका लेनोवो, निगेटिव

नहीं है विस्तार की योजना

विदर्भ में आने से महिंद्रा एंड महिंद्रा का ट्रैक्टर संयंत्र है, लेकिन यहां पैदल मात्र 3 प्रतिशत ही है। 90 प्रतिशत योजनेट हमें विदर्भ के बाहर से ही मंगाने पड़ते हैं, जिससे लागत खासी बढ़ जाती है। ऐसी ही दूसरे निर्माताओं को देखते हुए योजनों विदर्भ में अपने अपनी विस्तार योजनाएं नहीं बना रहीं।
-विजय काळमेघ, महाप्रबंधक प्रोडक्शन, महिंद्रा एंड महिंद्रा

सप्लायर बेस नहीं

विदर्भ भविष्य में एक ऑटो हब के रूप में उभर सकता है। इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन योजनों को योजना अभी यहां आने की नहीं है, क्योंकि यहां सप्लायर बेस नहीं है। हमें ऑटो योजनेट बाहर से ही मंगाने पड़ेंगे। इसके अलावा यहां योजनेटेड पुलिसें भी नहीं हैं। योजनों की नीतियों और नियमों के अनुसार ऑटो योजनेट उसमें से ही मंगाए जाते हैं।
- महेश कोठारी, एडमीनिस्ट्रेटिव डायरेक्टर, फाल्कनेक्स (ऑटो सेक्टर) फाल्कनेक्स

ऑटो स्टील उपलब्ध है

विदर्भ भारत के मध्य में है, लेकिन ऑटो उद्योग के लिए जरूरी माल यहां उपलब्ध नहीं है। जरूरी माल में अहम ऑटो स्टील होता है, जो यहां की खदानों उपलब्ध नहीं रहता पाती। हमें आयात करना पड़ेगा। राज्य सरकार को निवेश पिटो व्यवस्था भी शुरू करनी चाहिए।
-सुरिंदर कपूर, डिरेक्टर, एचईएमए एंड पेसमेकर एंड एसो., भारत सिक्स सि.

नए उद्योगों को मिलेगी छूट

नई औद्योगिक नीति के तहत नए उद्योगों को राज्य सरकार छूट देगी। इसके आलावा भी कई और सहूलियतें उद्योगों को मिलेंगी। विदर्भ में यदि ऑटो कंपनियां आती हैं, तो यह एक स्वस्थतापूर्ण शुरुआत होगी।
- मनु कुमार श्रीवास्तव, डिविजनल कमिश्नर, इंडस्ट्रीज मंत्रालय एमपीसीबी

बड़े पैमाने पर मिलेगा रोजगार

विदर्भ में विकास मैन पॉवर उपलब्ध है। पुराने को लघुनीती ज्ञान है, लेकिन उद्योगों के आकार में ये पारंगत नहीं आते हैं। यदि बड़ी ऑटो कंपनियां यहां आती हैं, तो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों ही रूप में बड़े पैमाने पर लोगों को रोजगार मिलेगा।
-मयंक शुक्ला, एसआईटीपी इंडस्ट्रीज एसोसिएशन विलास

गारंटी मिले

विदर्भ में बिजली, पानी, परिवहन, रेलवे की अच्छी सेवा है, लेकिन उद्योगों को सब्सिडी के विज्ञापनों की गारंटी मिलनी चाहिए। यहां सबसिड़ी आड़ा बहुत है। योजनों को यहां नहीं। बाद्यमुख इसलिए विदर्भ इंडस्ट्री में पीछे है। उद्योग शुरू होने के पूर्व लेबलाटी का विरोध व शुरू होने के बाद टैक्स पुलिसों की शुरुआत की शिकायतें होती है। सरकार को उद्योगों की आड़ा अनुकूल कर देनी है। इन समस्याओं के तीव्र निवारण का मंत्रालय निर्माण चाहिए।
-रमेश चांडक, एमडी व सीईओ, केईसी इंटरनेशनल

खाटे का काम पसंद नहीं

किसी उद्योग सीमेंट बनाने से अनुमोल नहीं बढ़ायेगा। उद्योगों को उपाड़ से उपाड़ सुविधा व इंसेंटिव मिलना चाहिए। मुंबईकरों में जो उद्योग शुरू हुए, उन्हें यहां से उपाड़ बिजनेस पहोले टाउने में मिल रहा है। बिजनेस नहीं मिलेगा, तो खाटे में साल खाला पलेंद नहीं। बड़ा उद्योग लाने के बाद उसके लिए कनेक्टर पुलिस भी लाना चाहिए। छोटे-बड़े सभी उद्योगों को सुविधा मिलनी चाहिए।
-सुनील गुप्ताटे, मोहना प्रबंध निदेशक, सुनील इंडीज प्रा. लि.